



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37008

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1513 वर्ष 2026

महेंद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दीपक सिंह, जी.एस. चौहान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अभिलेख में लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 10.5.2025 की एफ.आई.आर. बी.एन.एस. की धारा 87, 137(2), 61(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 51/6 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। जब पीड़िता को बरामद किया गया, तो बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना वाले दिन वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ रामनगर गई थी और उन्होंने एक मंदिर में विवाह किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और वह आवेदक के साथ रहना चाहती है। हालांकि उसकी चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष पाई गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पीड़िता के बयानों के अनुसार वह सहमत पक्ष प्रतीत होती है और आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने हेतु कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे वह यह भी प्रस्तुत करता है कि आवेदक 14.05.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक **महेंद्र** को वाद अपराध संख्या 94/2025 में, बीएनएस की धारा 65(1), 87, 137(2) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 51/6 के तहत, पुलिस स्टेशन छजलेट, जिला मुरादाबाद में, निजी मुचलके पर और दो स्थानीय जमानतों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका आवेदक पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, जिससे उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

18 फरवरी, 2026

मुस्तकीम.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”